Regd. No. CHD/0093/2009–2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 1, 2011
(PHALGUNA 10, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 1st March, 2011

No. 4—HLA of 2011/10.—The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 4—HLA of 2011

THE PUNJAB LAND REVENUE (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

further to amend the Punjab Land Revenue Act, 1887, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Act, 2011. Short title.

2. In section 98 of the Punjab Land Revenue Act, 1887,— Amendment of section 98 of Punjab Act 17 of 1887.

(i) in caluse (k), for the sign " ; " existing at the end, the sign " . " shall be substituted; and

(ii) clause (1) shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

For recovery of the amount due from the former Chief Ministers/Ministers during the terms of their office except amount taken for house building and car advance, a provision in section 98 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 was made *vide* Act No. 9 of 1994 with effect from 1st January, 1980.

1. Now to recover the out-standing amount against a Minister, Leader of Opposition, Speaker, Deputy Minister, Deputy Speaker, Chief Parliamentary Secretary, Parliamentary Secretary or Member of Legislative Assembly a provision is being made separately in "The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of members) Act, 1975". To avoid duplication clause (I) of Section 98 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 is to be deleted, hence the bill for amendment.

SAT PAL,
Revenue Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 1st March, 2011

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 4-एच० एल० ए०

पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2011

पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 98 में,— 1887 के पंजाब अधिनियम 17 की धारा 98 का संशोधन।

(i) खंड (ट) में, अंत में विद्यमान चिह्न " ; " के स्थान पर "। " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) खंड (ठ) का लोप कर दिया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों से उनके मंत्री काल में देय बनी राशियों की वसूली भवन निर्माण ऋण तथा मोटर कार ऋण को छोड़कर करने के लिए पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 98 में 1994 के अधिनियम 9 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1980 से प्रावधान किया गया था।

2. अब मंत्री, विपक्ष के नेता, अध्यक्ष, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव या विधान सभा सदस्य के विरुद्ध बकायाजात की वसूली हेतु "हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1975" में अलग से प्रावधान किया जा रहा है। दोहरे प्रावधान से बचने के लिए पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 98 के खण्ड (ठ) को लोप किया जाना है। अत: संशोधन के लिए बिल की आवश्यकता है।

सतपाल,
राजस्व मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
1 मार्च, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।

48351—H.V.S.—H.G.P., Chd.